employment opportunities created in the country during 1992-93 are likely to the order of 6 million;

(b) if so, the State-wise and occupation-wise break up of the jobs created during the year; and

(c) whether Government have any estimate of the contraction of employment opportunities in the same year?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) The estimate of additional employment opportunities likely to have been generated in the country during 1992-93 has been published in the Annual Plan (1993-94) document as well as in the Economic Survey—1993-94. This has not been communicated to the State Governments separately.

(b) No State-wise or occupation-wise estimates of the additional employment generated have been made.

(c) Employment opportunities are estimated to have grown by around 6 million during 1992-93. As such there has been no contraction in overall employment.

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सौराष्ट्र क्षेत्र को आवंटित की गई धन राशि

1975. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार सौराष्ट्र क्षेत्र को विभिन्न जिलेवार योजनाओं के लिए 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहयता के रूप में कुल कितनी राशि आवंटित की गई,

(ख) क्या सरकार ने 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रम की गत तीन वर्षों में कोई समीक्षा कराई है,

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त वर्षों के दौरान रखे गये लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) योजना आयोग 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से निधियों का आवंटन नहीं करता । राज्य सरकारें अपनी वार्षिक योजनाओं में सेक्टर शीर्षों के तहत 20-सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न मदों के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है ।

(ख) जी हां । पूरे गुजरात राज्य के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा वास्तविक निष्पादन की समीक्षा की गई है ।

(ग) और (घ) वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 के दौरान मासिक मानीटरिंग के लिए पहचान किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत मदों के संबंध में गुजरात के लक्ष्य और उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक अनुपत्र संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र सं० 47]

सौराष्ट्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग

1976. **श्री चिमन भाई हरि भाई शुक्ल :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है,

(ख) क्या गरीबी के उन्मूलन हेतु आरम्भ किये गये अथवा आरम्भ किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है,

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है, और

(घ) सरकार द्वारा इन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए अपनाये गये विशेष उपायों का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) योजना आयोग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या और अनुपात का अनुमान केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लगाता है । किसी राज्य के भीतर क्षेत्रीय स्तर पर नहीं ।

(ख) से (घ) गुजरात सरकार गरीब परिवारों के जीवन स्तर और आय में सुधार लाने के लिए कई कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है । इनमें आय में वृद्धि करने और रोजगार अवसरों का सृजन करने के कार्यक्रम शामिल हैं जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), और नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) । इसके अतिरिक्त अनु०जा०/अनु० जन० जाति परिवारों के हित के लिए अनु० जा० हेतु विशेष घटक योजना (एस सी पी) और जनजातीय उपयोजना (टी एस पी) क्रियान्वित की जा रही है । आई आर डी पी और जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन और प्रभाव का कई संगठनों द्वारा मूल्यांकन और सरकार द्वारा मानीटरिंग की गई है । इन कार्यक्रमों का लाभग्राहियों की आय पर सकारात्मक प्रभाव रहा ।

Capital Investment on Agriculture and Indultrial Sectors

1977. SHRI BHUPINDER SINGH MANN : Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) what was the total capital investment on agriculture and industrial sectors during 1993-94 and how it compares with the previous year;

(b) whether the gap in investment in both the sectors will be brought closer in the coming years in view of the latest developments in the global economy and agriculture would be given priority like other sectors;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) The latest year for which sectorwise gross capital formation estimates are available is 1992-93. Estimates for capital investment in agriculture and industrial sectors are not available for the year 1993-94.

(b) to (d) The Agriculture & Allied Activities Sector is a priority sector in the Eighth Plan. Investment gap between Agriculture & Allied Activities Sector in the facturing sector is targetted to be reduced in the Eighth Plan (1992—97) as compared to the Seventh Plan. The share of Agriculture & Allied Activities Sector in the total investment is targetted to increase from 11.23 per cent in the Seventh Plan lo 18.65 per cent in the Eighth Plan.

Proposals for Energy Commission and Minimum Agricultural Tariff

1978. SHRI VIREN J. SHAH :

SHRI PRAMOD MAHAJAN :

DR. NAUNIHAL SINGH :

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that National Development Council (NDC) Committee on Power headed by Shri Sarad Pawar has recommended the constitution of an all-powerful Energy Commission of the level of a Cabinet Committee, under the Chairmanship of the Prime Minister to evolve long-term policy/strategy at the national level;

(b) if so, the details lhereof and whether the recommendation has been approved by the NDC Committee;